ई संदेश

28 मई, 2026 | अंक - 207

सात दिन, सात पृष्ठ

- जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप में उत्तर प्रदेश का दबदबा, मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत
- सरकार की विकास परियोजनाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगारपरक विजन से देवरिया को मिले नए आयाम
- पारदर्शी नीतियों और विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी से देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश
- श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और वैश्विक रोजगार के संकल्प से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रही अभूतपूर्व शक्ति
- वैश्विक आयुष वेलनेस डेस्टिनेशन हो उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री
- उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने में राज्य कर विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री
- कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और फसल विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय: मुख्यमंत्री
- जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास का प्रभावी केन्द्र बनाएं, आधुनिक तकनीक से सुरक्षा हो मजबूत: मुख्यमंत्री
- आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश से ही सिद्ध होगा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प: मुख्यमंत्री
- प्रयागराज में विकसित की गई बेहतरीन अवस्थापना सुविधाओं का सही ढंग से अनुरक्षण किया जाए: मुख्यमंत्री

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप में उत्तर प्रदेश का दबदबा

मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 मई 2026 को जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में रोइंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया के तत्वावधान में आयोजित 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप (अण्डर-19) के समापन समारोह में विजेता और उप-विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ताल में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप के सफल आयोजन पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। प्रतियोगिता में देश के 20 राज्यों से आए लगभग 300 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विजन को मजबूती से आगे बढ़ाया।

अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए अद्वितीय कौशल और टीम भावना की सराहना की। प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी की पंक्तियों 'लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती' और वेदों के मूलमंत्र 'चरैवेति चरैवेति' का उल्लेख करते हुए खिलाड़ियों को निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा दी गई। वर्तमान में स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स और अत्याधुनिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत विश्व मानचित्र पर एक बड़ी रोइंग शक्ति के रूप में स्थापित हुआ।

गोरखपुर का रामगढ़ताल वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय वॉटर स्पोर्ट्स के एक बड़े हब के रूप में अपनी नई पहचान बना चुका है, जहाँ एशियन गेम्स-2026 की तैयारी हेतु भारतीय महिला रोइंग टीम का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया। वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी महिला रोइंग टीम के प्रशिक्षण हेतु रामगढ़ताल का चयन किया गया है, जिसके दृष्टिगत प्रशासन को सभी आवश्यक अत्याधुनिक व्यवस्थाएं, श्रेष्ठ कोच और एक्सपर्ट्स की सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई सुदृढ़ खेल नीति के माध्यम से खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस नीति के तहत इण्टरनेशनल और नेशनल चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले प्रदेश के 534 खिलाड़ियों को अब तक विभिन्न सरकारी विभागों में डिप्टी एस0पी0 जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं और 500 अन्य पदों पर भर्ती की कार्यवाही गतिमान है। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव ने भी प्रदेश में निर्मित हो रहे सुदृढ़ खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक खेल विश्वविद्यालय की सराहना की।

सरकार की विकास परियोजनाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगारपरक विजन से देवरिया को मिले नए आयाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22 मई 2026 को जनपद देवरिया में 655 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 19 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरान्त आयोजित भव्य कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस पावन अवसर पर उन्होंने विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, प्रतीकात्मक चेक, आवास की चाभियाँ और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल प्रदान कीं। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा बच्चों का अन्नप्राशन एवं महिलाओं की गोदभराई की। कार्यक्रम के दौरान देवरिया की विकास यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गयी।

जनपद देवरिया को पूज्य देवरहा बाबा की पावन तपोभूमि तथा सन्त बाबा राघवदास की कर्मभूमि के रूप में नमन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2014 के उपरान्त देश ने विकासपरक विजन के साथ नए भारत का दर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने सदैव माना कि विकास की गति जितनी तीव्र होगी, उसका सीधा लाभ आमजन को उतनी ही तेजी से प्राप्त होगा। अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना विकास और रोजगार का सृजन संभव नहीं है, जिसके दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों के विकास संबंधी प्रस्तावों पर सरकार ने तत्काल भारी धनराशि जारी की।

अतीत में गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान करते हुए वर्तमान में 04-लेन सड़क का निर्माण पूर्ण कर दोनों जनपदों के बीच की दूरी तथा समय को कम किया गया। देवरिया में बाईपास निर्माण के साथ-साथ इस मार्ग का विस्तार बलिया तक किया जा रहा है। यह शानदार कनेक्टिविटी आगे चलकर पड़रौना, कसया, देवरिया और मऊ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगी, जिससे वाराणसी व लखनऊ की राह सुगम होगी। इसके साथ ही यह मार्ग गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाने वाले 06-लेन एक्सप्रेस-वे का हिस्सा बनकर क्षेत्रवासियों की यात्रा को अत्यंत सुगम बनाएगा।

गति को ही प्रगति का मुख्य आधार बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देवरिया में पूज्य महर्षि देवरहा बाबा के नाम पर भव्य सरकारी मेडिकल कॉलेज पूरी तरह निर्मित होकर उत्कृष्ट ओ0पी0डी0 सेवाओं के साथ संचालित हुआ, जबकि नए जिला अस्पताल का निर्माण कार्य भी प्रक्रियाधीन है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर हुनरमंद बनाने तथा देश-विदेश में रोजगार के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराने के लिए देवरिया में आई0टी0आई0 का भव्य निर्माण कराया जा रहा है, जो आगामी समय में स्किल डेवलपमेण्ट का एक बड़ा केंद्र बनेगा।

वर्ष 2017 से पूर्व की कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अतीत में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक माफिया का बोलबाला रहता था, पर्वों से पूर्व उपद्रव होते थे और गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए जाते थे। वर्तमान समय में 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज' तथा 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाएँ नए उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान बनीं, जहाँ बेटियाँ सुरक्षित माहौल में नाइट शिफ्ट के दौरान भी उद्योगों में कार्य कर रही हैं। गन्ना किसानों को 400 रुपये प्रति कुन्तल की ऐतिहासिक दर से भुगतान मिल रहा है और कुशीनगर में भव्य कृषि विश्वविद्यालय बनकर पूरी तरह तैयार हुआ, जो नए शैक्षणिक सत्र से संचालित होने जा रहा है।

वैश्विक परिस्थितियों के कारण बिटुमिन की आपूर्ति प्रभावित होने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ग्रामीण और राजमार्ग कनेक्टिविटी के लिए इण्टरॉकिंग तथा सी0सी0 (सिमेंटेड कंक्रीट) मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए, जो आगामी 50 वर्षों के लिए मरम्मत की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मन्दिर के निर्माण सहित काशी, मथुरा-वृन्दावन, नैमिषारण्य, माँ विन्ध्यवासनी धाम और प्रयागराज में विरासत व विकास का अद्भुत संगम आज उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान बना, जिससे संपूर्ण देश-दुनिया में प्रदेश के निवासियों का गौरव बढ़ा।

पारदर्शी नीतियों और विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी से
देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22 मई 2026 को लखनऊ में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अन्तर्गत 17 प्रमुख निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र वितरित करने के उपरान्त आयोजित भव्य कार्यक्रम को सम्बोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निवेशकों ने उत्तर प्रदेश के ब्रॉण्ड एम्बेस्डर के रूप में प्रदेश की नई और सकारात्मक छवि को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया। नए उत्तर प्रदेश ने अपनी दूरदर्शी नीतियों के बल पर स्वयं को टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेण्ट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है, जिसकी बदलती तस्वीर राज्य के प्रत्येक जनपद की प्रगति को प्रदर्शित कर रही है।

यीडा क्षेत्र में दिखाई दे रहे बड़े सकारात्मक परिवर्तनों को नए उत्तर प्रदेश की वास्तविक तस्वीर बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने आवंटन पत्र प्राप्त करने वाले सभी निवेशकों से अपनी औपचारिकताओं को तेजी से पूर्ण कर समय से निवेश करने का आह्वान किया। निवेशकों को एनसीआर के बाहर विस्तृत उत्तर प्रदेश को देखने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद कुशीनगर, बलिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, चन्दौली, चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, महोबा एवं ललितपुर आदि क्षेत्रों में भी उद्योगों के अनुकूल उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं का शानदार अनुभव प्राप्त होगा।

औद्योगिक विकास के लिए सुरक्षा को पहली अनिवार्य शर्त बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्यमियों को बिना किसी रोक-टोक व लेन-देन के एक स्पष्ट पॉलिसी बनाकर सुगमतापूर्वक लाभ और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिस जेवर क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पूर्व विभिन्न प्रकार के जघन्य अपराध घटित होते थे, वर्तमान में वहीं भारत का सबसे बड़ा 'नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट' बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से संपन्न हुआ। अत्याधुनिक कार्गो और एम0आर0ओ0 (मैन्टेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल) सुविधा से सुसज्जित इस भव्य एयरपोर्ट से आगामी 15 जून से घरेलू विमान सेवाएं और उसके तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय सेवाएं भी सफलतापूर्वक प्रारम्भ होने जा रही हैं।

क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यीडा क्षेत्र में उत्तर भारत की सबसे बड़ी सेमीकण्डक्टर चिप बनाने वाली अत्याधुनिक यूनिट की आधारशिला रखी जा चुकी है और सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एम0एस0एम0ई0 पार्क, हैण्डीक्राफ्ट पार्क और विशाल डेटा सेण्टर पार्क का विकास पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है।

वर्ष 2017 से पूर्व की बदहाल कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अतीत में प्रदेश के भीतर सत्ता के समानान्तर माफिया का एक क्रूर साम्राज्य सक्रिय था, प्रत्येक जनपद में भय व दहशत का माहौल रहता था और 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' का बोलबाला था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में अग्रणी स्थान पर स्थापित हुआ, जहाँ देश के कुल एक्सप्रेस-वे का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है और 04 लाख किलोमीटर का विशाल सुदृढ़ सड़क नेटवर्क विद्यमान है।

एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाते हुए प्रदेश में क्रियाशील एयरपोर्ट्स की संख्या 02 से बढ़कर 16 तक पहुँच गई, जिनमें 05 भव्य इण्टरनेशनल एयरपोर्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के पास 16 हजार किलोमीटर का सुदृढ़ रेल नेटवर्क है और ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का महत्वपूर्ण जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नोएडा देश के एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है, जहाँ व्यापार के लिए फ्रेट कॉरिडोर, एयर कनेक्टिविटी और शानदार सड़कों का बेजोड़ संगम उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के पास देश की पहली अत्याधुनिक रैपिड रेल, वाराणसी से हल्दिया के बीच देश का पहला सफल इनलैण्ड वॉटर-वे और 07 प्रमुख शहरों में मेट्रो का शानदार संचालन हो रहा है।

क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यीडा क्षेत्र में उत्तर भारत की सबसे बड़ी सेमीकण्डक्टर चिप बनाने वाली अत्याधुनिक यूनिट की आधारशिला रखी जा चुकी है और सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एम0एस0एम0ई0 पार्क, हैण्डीक्राफ्ट पार्क और विशाल डेटा सेण्टर पार्क का विकास पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है।

वर्ष 2017 से पूर्व की बदहाल कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अतीत में प्रदेश के भीतर सत्ता के समानान्तर माफिया का एक क्रूर साम्राज्य सक्रिय था, प्रत्येक जनपद में भय व दहशत का माहौल रहता था और 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' का बोलबाला था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में अग्रणी स्थान पर स्थापित हुआ, जहाँ देश के कुल एक्सप्रेस-वे का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है और 04 लाख किलोमीटर का विशाल सुदृढ़ सड़क नेटवर्क विद्यमान है।

एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाते हुए प्रदेश में क्रियाशील एयरपोर्ट्स की संख्या 02 से बढ़कर 16 तक पहुँच गई, जिनमें 05 भव्य इण्टरनेशनल एयरपोर्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के पास 16 हजार किलोमीटर का सुदृढ़ रेल नेटवर्क है और ईस्टर्न एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का महत्वपूर्ण जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नोएडा देश के एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है, जहाँ व्यापार के लिए फ्रेट कॉरिडोर, एयर कनेक्टिविटी और शानदार सड़कों का बेजोड़ संगम उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के पास देश की पहली अत्याधुनिक रैपिड रेल, वाराणसी से हल्दिया के बीच देश का पहला सफल इनलैण्ड वॉटर-वे और 07 प्रमुख शहरों में मेट्रो का शानदार संचालन हो रहा है।

आज निर्गत किए गए इन ऐतिहासिक अलॉटमेण्ट लेटर्स के माध्यम से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15,000 से अधिक नवीन रोजगार के शानदार अवसर सृजित होंगे, जो मुख्य रूप से रिन्युएबल एनर्जी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, आई0टी0 एण्ड डेटा प्रोसेसिंग, एपैरल, एम0एस0एम0ई0 और एडवान्स्ड इण्डस्ट्रियल कम्पोनेण्ट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में निवेश को एक नई व तीव्र गति प्रदान करेंगे। इसके अंतर्गत सी0ई0एस0सी0 ग्रीन पावर लिमिटेड द्वारा लगभग 3,805 करोड़ रुपये के निवेश से यीडा क्षेत्र में सोलर सेल एवं सोलर पावर प्लाण्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है, जिससे लगभग 5,000 रोजगार सृजित होंगे।

इसके साथ ही, इण्टीग्रेटेड बैटरीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 1,146 करोड़ रुपये के निवेश से 04 गीगावॉट क्षमता की अत्याधुनिक एडवान्स्ड बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित कर रही है। आई0टी0, आई0टी0ई0एस0 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कई अन्य अग्रणी कम्पनियों में एस0ए0ई0एल0 सोलर पी-6 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 8,000 करोड़ रुपये के निवेश से सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाई और एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड द्वारा लगभग 4,500 करोड़ रुपये के भारी निवेश से ट्रैक्टर एवं निर्माण उपकरण मैन्युफैक्चरिंग प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से 4,000 युवाओं को सीधे रोजगार प्राप्त होगा।

कार्यक्रम के मुख्य चरण में मुख्यमंत्री जी ने विख्यात कम्पनियों के प्रतिनिधियों को अपने कर-कमलों से भूमि आवंटन पत्र सौंपकर राज्य के औद्योगिक विकास में भागीदारी हेतु उनका स्वागत किया।

श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और वैश्विक रोजगार के संकल्प से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रही अभूतपूर्व शक्ति

ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 23 मई 2026 को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रस्तावित परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान राज्य में श्रमिक कल्याण, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन को और अधिक व्यापक व परिणामोन्मुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए 'बाल श्रमिक विद्या योजना' को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, तकनीक आधारित 'सेवामित्र व्यवस्था' को और अधिक प्रभावी बनाने, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े औद्योगिक शहरों में अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केन्द्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के निर्देश दिए।

श्रमिकों के अप्रतिम योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति हैं। कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर उन्हें विद्यालयों से जोड़ा जाए। वर्ष 2020 में प्रारम्भ की गई 'बाल श्रमिक विद्या योजना' के अन्तर्गत 08 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। पूर्व में यह योजना मात्र 20 जनपदों में संचालित थी, जिसे अब नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने की स्वीकृति दी गई।

' सेवामित्र व्यवस्था' को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने इसे और अधिक प्रभावी तथा जनोपयोगी बनाने पर बल दिया। वर्ष 2021 से संचालित इस व्यवस्था के तहत नागरिक मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल अथवा कॉल सेन्टर के माध्यम से घरेलू सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में पोर्टल पर 1,097 सेवा प्रदाता, 5,049 सेवामित्र और 54,747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं। पारदर्शिता लाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए अब सरकारी विभागों में भी आवश्यकता के अनुसार सेवामित्र व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

श्रम विभाग में हुए संस्थागत सुधारों के फलस्वरूप प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड 32,583 कारखाने पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से अप्रैल 2017 के बाद रिकॉर्ड 18,407 नए कारखानों का पंजीकरण हुआ। विभाग को बी0आर0ए0पी0 के क्रियान्वयन में 'TOP ACHEIVER' के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है तथा उद्योग समागम 2025 में श्रम क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केन्द्रों यानी 'लेबर अड्डों' को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए ताकि इन्हें केवल श्रमिकों के एकत्रीकरण स्थल के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रमिक सहायता एवं सुविधा केन्द्र के रूप में संचालित किया जा सके।

कौशल विकास की दिशा में जनपद कानपुर के विष्णुपुरी में 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान आकार ले रहा है, जहां कारपेन्टरी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, पेन्टर और बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन जैसे विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेनाझाबर में 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाले एक भव्य छात्रावास का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया।

उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 2025 में गठित 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' तेजी से कार्य कर रहा है, जिसे विदेश मंत्रालय से भर्ती एजेंसी का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में आयोजित रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से 27,555 युवाओं का चयन किया गया, जिनमें 2,300 युवाओं का चयन विदेशों में रोजगार हेतु हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 3,030 रोजगार मेलों के माध्यम से 3,74,776 अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री जी ने इन रोजगार मेलों को उद्योगों की वास्तविक मांग से जोड़ने तथा इस पूरी प्रक्रिया को प्रसिद्ध सरदार वल्लभभाई पटेल इण्डस्ट्रियल एण्ड एम्प्लॉयमेंट ज़ोन से संबद्ध करने के निर्देश दिए।

युवाओं को वैश्विक रोजगार अवसरों का लाभ दिलाने के लिए जर्मनी, जापान और स्लोवाक गणराज्य सहित विभिन्न देशों में संभावनाएं चिन्हित की गई हैं, जिसके लिए जापानी, जर्मन और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु समझौते संपन्न हुए। इसी डिजिटल क्रांति के अंतर्गत रोजगार संगम पोर्टल में अब ए0आई0 (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित सेवाओं, digital जॉब मैचिंग और ऑनलाइन काउन्सलिंग प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

वैश्विक आयुष वेलनेस डेस्टिनेशन हो उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 मई 2026 को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में आयुष विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश में 'आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस नीति-2026' को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश को केवल पारंपरिक उपचार आधारित व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए आयुष, योग, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और अत्याधुनिक वेलनेस सेवाओं के बेहतरीन समन्वय से राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। आयुष सेवाओं को आधुनिक प्रबन्धन, कड़े गुणवत्ता मानकों और पर्यटन से जोड़ते हुए एक ऐसा सुदृढ़ मॉडल तैयार करने पर बल दिया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ राज्य में रोजगार और औद्योगिक निवेश को भी नई व तीव्र गति प्राप्त हो सके।

राज्य की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, आयुर्वेद एवं योग की प्राचीन परम्परा तथा धार्मिक पर्यटन सर्किट को आयुष वेलनेस सेक्टर से सीधे जोड़ने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाराणसी, अयोध्या और मथुरा जैसे प्रमुख पावन धार्मिक स्थलों के आसपास वेलनेस और हीलिंग आधारित उच्चस्तरीय पर्यटन विकसित किए जाने की व्यापक सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। इसी दूरदर्शी सोच के अंतर्गत सभी आयुष संस्थानों को मात्र उपचार केन्द्रों के रूप में ही नहीं, बल्कि वेलनेस, उत्कृष्ट प्रशिक्षण, उच्च अनुसंधान और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के प्रमुख केन्द्रों के रूप में विकसित करने के निर्देश जारी किए गए।

बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 3,953 आयुष स्वास्थ्य इकाइयाँ, 1,034 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, 225 सक्रिय योग वेलनेस सेण्टर और 19 प्रतिष्ठित आयुष चिकित्सा महाविद्यालय पूरी सफलता के साथ संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इन सभी आयुष सेवाओं का विस्तार अत्यंत गुणवत्तापूर्ण और मानकीकृत स्वरूप में किए जाने की आवश्यकता जताई, जिसके लिए पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के माध्यम से आधुनिक आयुष वेलनेस सेण्टर, 100 शैय्या वाले एकीकृत आयुष चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा वर्तमान आयुष कॉलेजों के उन्नयन की दिशा में चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही गतिमान की गई।

प्रस्तावित नई नीति के विभिन्न बिन्दुओं पर हुई विस्तृत चर्चा के अंतर्गत एकीकृत सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस, आयुष वेलनेस एवं चिकित्सा केन्द्र, प्रशिक्षण युक्त एकीकृत संस्थान तथा आयुष कॉलेज आधारित मॉडल विकसित करने का खाका प्रस्तुत किया गया, जिसमें पंचकर्म, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, डिजिटल हेल्थ सेवाओं तथा अनुसंधान एवं नवाचार की गतिविधियों को भी प्रमुखता से शामिल किया गया। आयुष आधारित वेलनेस इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने निवेशकों को एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के माध्यम से त्वरित स्वीकृतियाँ उपलब्ध कराने तथा सभी परियोजनाओं के ससमय क्रियान्वयन के लिए एक स्पष्ट व समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस प्रस्तावित नीति में निवेश आधारित आकर्षक सब्सिडी, संचालन सम्बन्धी प्रोत्साहन, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट तथा रोजगार सृजन आधारित विशेष प्रोत्साहन का प्राविधान किया गया है, जबकि आयुष शोध, नवाचार तथा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए भी विशेष रियायतें प्रस्तावित की गईं।

क्षेत्रीय संतुलन और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार हेतु मुख्यमंत्री जी ने मीरजापुर, गोण्डा, मेरठ, आगरा एवं बस्ती मण्डलों में एकीकृत आयुष महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में अत्यंत तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि इन संस्थानों को आधुनिक आयुष चिकित्सा, प्रशिक्षण और उच्च अनुसंधान के उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए आयुष चिकित्सा संस्थानों में ओ0पी0डी0 सेवाओं को अधिक बेहतर बनाने, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पंचकर्म जैसी पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया ताकि आयुष सेवाओं को जनविश्वास से जोड़ते हुए मरीजों को बेहतर उपचार प्राप्त हो सके।

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर में शोध एवं नवाचार गतिविधियों को और अधिक गति देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थायी फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने तथा आयुष की पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय को एक अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करने के कड़े निर्देश दिए ताकि उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में आयुष का नेतृत्व कर सके।

उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने में राज्य कर विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 25 मई, 2026 को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कर संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में राज्य कर विभाग की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए विभाग को राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करना होगा।

कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने जी0एस0टी0 पंजीयन, रिटर्न दाखिले, अपील निस्तारण और रिफण्ड जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी समाप्त करने की बात कही। उन्होंने व्यापारियों के साथ निरन्तर संवाद बनाए रखने, छोटे कारोबारियों को जागरूक करने तथा जिला एवं खण्ड स्तर तक करदाता सहायता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए कर चोरी रोकने के साथ-साथ वैध व्यापार को प्रोत्साहन देना आवश्यक बताया।

बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने जी0एस0टी0 और वैट मद में कुल 1,15,977 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत रहा। जी0एस0टी0 में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। जी0एस0टी0 बकाया के रूप में 2,658 करोड़ रुपये जमा हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक हैं। वैट बकाया के रूप में 800 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो गत वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से 2,071 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को कुल 1,98,071 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जी0एस0टी0 का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपये तथा वैट का लक्ष्य 48,115 करोड़ रुपये है। अप्रैल, 2026 में राज्य ने 10,896 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक रहा। ज़ोनवार समीक्षा में गौतमबुद्ध नगर ज़ोन ने 1,506 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के सापेक्ष सहारनपुर ज़ोन में 35.1 प्रतिशत और वाराणसी प्रथम ज़ोन में 33.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले ज़ोनो को विशेष कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

फर्जी फर्मों और कर चोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज की गई तथा 168 गिरफ्तारियां हुईं। 07 नवम्बर, 2025 को गठित एस0आई0टी0 की कार्रवाई के तहत 180 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई तथा न्याय-निर्णयन कार्रवाई से 2,250 करोड़ रुपये की मांग सृजित हुई। वर्ष 2025-26 में जी0एस0टी0 की 52,432 और वैट की 11,365 सहित कुल 63,797 अपीलों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में विचाराधीन कुल 20,697 अपीलों के भी समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सबसे अधिक जी0एस0टी0 करदाताओं वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में जी0एस0टी0 पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि मात्र 08 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन का है। राज्य में 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है। रिटर्न दाखिले में भी प्रदेश का मासिक औसत 93 प्रतिशत रहा, जो केन्द्र स्तर के 91 प्रतिशत के औसत से आगे है।

राज्य में जी0एस0टी0 रिफण्ड मामलों के निस्तारण की औसत अवधि 27 दिन रही, जो राष्ट्रीय औसत 48 दिन से काफी कम है। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के निर्देश दिए ताकि व्यापारियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित न हो। तकनीक आधारित कर प्रशासन के तहत 16 पैरामीटर निर्धारित कर 1.59 लाख वार्षिक रिटर्नों में मिसमैच डेटा पर विधिक कार्रवाई शुरू की गई। वर्ष 2025-26 में 1.33 लाख डीलरों की स्क्रूटनी के दौरान 2,369 करोड़ रुपये की मांग सृजित की गई तथा 345 करोड़ रुपये जमा कराए गए।

व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रमों को और व्यापक बनाने के क्रम में सभी 75 जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जी0एस0टी0 पंजीयन, रिटर्न फाइलिंग और जी0एस0टी0 2.0 सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई। जून, 2026 से राज्य कर विभाग द्वारा खण्ड स्तर पर भी संवाद कार्यक्रम चलाने की कार्ययोजना तैयार की गई। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि डेटा आधारित निगरानी और ए0आई0 आधारित विश्लेषण से कर प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियन्त्रण सम्भव होगा।

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और फसल विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 25 मई, 2026 को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में कृषि विभाग की विभिन्न प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में विशेष रूप से निर्देश दिए कि खरीफ-2026 की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक तथा तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्रीअन्न की खेती को प्रोत्साहित करने तथा सूखा सम्भावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्ययोजना तैयार रखने के कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि यू0पी0 इण्टरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर कृषि विभाग भी अपनी विशेषताओं की एक अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को समय-समय पर कृषि सम्बन्धी तकनीकी सलाह उपलब्ध कराने के लिए टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी और अन्य माध्यमों का व्यापक उपयोग करने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने आगामी जून माह से सभी विकास खण्डों में आयोजित होने वाली चौपालों के साथ ही अनिवार्य रूप से किसान मेला लगाने के निर्देश दिए ताकि प्रगतिशील खेती को बढ़ावा मिले। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों, विज्ञान केन्द्रों, मण्डियों और वेयरहाउस के आस-पास साफ-सफाई रखने, आवश्यकतानुसार रंगाई कराने तथा इन केन्द्रों तक अच्छी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क को प्रारम्भ करने की दिशा में तेजी लाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी और उनके डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए तथा संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। योजनाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और बढ़ाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को हर लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से मिलना चाहिए। उन्होंने बुन्देलखण्ड सहित जल संकट वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती और श्रीअन्न उत्पादन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के साथ समन्वय मजबूत करने पर बल दिया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराया जाए तथा बीमा दावों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए ग्लोबल मानकों का विशेष ध्यान रखने तथा मण्डी समितियों को आधुनिक, पारदर्शी और सुविधायुक्त बनाकर कृषि विपणन व्यवस्था को और मजबूत करने के कड़े निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में अधिकारियों द्वारा प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इसके तहत खरीफ-2026 में 110.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल और 302.62 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें धान का लक्ष्य 224.25 लाख मीट्रिक टन रखा गया। इसके अलावा, एग्रीस्टैक योजना के अन्तर्गत 24 मई, 2026 तक 2.29 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी होने, उर्वरक प्रवर्तन अभियान के तहत 4,025 छापे मारकर 81 लाइसेंस निलम्बित करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 99,032 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित किए जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई।

जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास का प्रभावी केन्द्र बनाएं, आधुनिक तकनीक से सुरक्षा हो मजबूत: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 25 मई, 2026 को लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए कि जेलों को केवल बंदी रखने का स्थान नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास का प्रभावी केन्द्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के सभी कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रशिक्षण, तकनीकी सुदृढ़ीकरण और पुनर्वास सम्बन्धी व्यवस्थाओं को और बेहतर किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आधुनिक तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को एक नई पहचान दी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने 'ओपेन जेल' की परिकल्पना को विशेष महत्व देते हुए इसे साकार रूप में लाने के लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल केवल पेशेवर अपराधियों और माफिया के लिए होनी चाहिए, जबकि छोटे अपराधों के लिए 'ओपन जेल' की व्यवस्था बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने जेलों में बंदियों की अत्यधिक संख्या (ओवरक्राउडिंग) को कम करने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा नए कारागारों व बैरकों के निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने विशेष मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्देश दिए कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त कैदियों, बच्चों के साथ जेल में बंद महिला कैदियों और जमानत राशि जमा न कर पाने के अभाव में जेल में बंद कैदियों की एक अलग सूची तत्काल तैयार की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बहुमंजिला कारागारों के निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही और चेतावनी दी कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने जेलों के भीतर तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया।

सुधारात्मक प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि कारागारों में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और उत्पादन गतिविधियों को और व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए ताकि बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने जेलों में बंदियों के स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए योग, खेलकूद, कृषि और गौसंवर्धन जैसी रचनात्मक गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बंदियों की समयपूर्व रिहाई की व्यवस्था को तेज किया गया, जिससे वर्ष 2022 से 2026 के बीच 3,846 बंदियों को समयपूर्व रिहाई मिली। वर्तमान में प्रदेश की जेलों में ओवरक्राउडिंग दर घटकर 1.03 रह गई है तथा अमेठी, महोबा, हाथरस सहित छह जनपदों में नए कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तकनीकी सुरक्षा के तहत प्रदेश की जेलों में 6,200 सी0सी0टी0वी0 कैमरे, 30 ड्रोन कैमरे, 195 बॉडी वॉर्न कैमरे और 83 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। प्रदेश की 37 जेलों में 'वन जेल वन प्रोडक्ट' आधारित उद्योग संचालित होने के साथ-साथ 17 जेलों में गौशालाएं भी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं।

आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश से ही सिद्ध होगा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 मई, 2026 को नगर निगम, लखनऊ की 413 करोड़ रुपये लागत की 342 जनकल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में जितनी अच्छी सुविधाएं होंगी, उतनी ही तेजी से राज्य वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कड़े निर्देश दिए कि स्वच्छता केवल नगर निगम के महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिक जवाबदेही का भी आधार है, इसलिए सभी नागरिक अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकें तथा गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करें। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बन्द करने, नालियों में कूड़ा न फेंकने और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचाने की सख्त हिदायत दी।

वैश्विक और घरेलू ऊर्जा संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों और सभी नगर निकायों से बिजली की अत्यधिक बचत करने की गम्भीर अपील की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि नागरिक केवल आवश्यकतानुसार ही बिजली का उपयोग करें, घरों में अनावश्यक रूप से ए0सी0, पंखे तथा लाइटें न चलाएं और सजावट के लिए लगी लाइटों को तत्काल बन्द कर दें। उन्होंने नगर निकायों तथा पंचायतों को निर्देशित किया कि वे नागरिकों के हित में ऊर्जा संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाएं और संकट के इस समय में पावर कॉरपोरेशन का पूर्ण सहयोग करें। मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा संकट को लेकर किसी भी प्रकार के बहकावे में न आने और अफवाह न फैलने देने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम की ढांचागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन और सी0एम0 ग्रिड योजना के अन्तर्गत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप बनने वाली सड़कों में यूटिलिटी डक्ट बनाने के निर्देश दिए ताकि पाइप लाइन और केबल के लिए बार-बार सड़क न खोदनी पड़े। इसके साथ ही सड़कों पर पार्किंग स्पेस, फुटपाथ तथा स्ट्रीट लाइटों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में स्टॉर्म वॉटर की समस्या और जलभराव का स्थायी समाधान करने के लिए नगर निगम और नगर विकास विभाग को मिलकर एक बेहतरीन कार्ययोजना के तहत कार्य करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नगर निगम का इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है, जिसका उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेण्ट, स्वच्छता और सुरक्षा की निगरानी के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में लगातार किया जाए। उन्होंने लखनऊ में बनने वाली मॉडल गौशाला में गौ सेवा के साथ-साथ सी0एन0जी0 और कम्पोस्ट निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि 'वेस्ट को वेल्थ' में बदलने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके।

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 'हमारे सपनों का लखनऊ, स्वच्छ-सुन्दर-समर्थ लखनऊ' पुस्तिका का विमोचन किया और कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बैठक में जानकारी दी गई कि लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निकायों का तीन वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा हो गया, जिसमें लखनऊ नगर निगम ने देश में तीसरी स्वच्छता रैंकिंग प्राप्त करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आवास विभाग के माध्यम से लखनऊ में 10,000 लोगों की क्षमता वाले एक भव्य कन्वेंशन सेण्टर के निर्माण की स्वीकृति और टेण्डर प्रक्रिया पूरी होने की बात भी सामने आई। सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में 65 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के आवास, आयुष्मान भारत योजना और निःशुल्क राशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के कल्याण का सपना साकार किया गया।

प्रयागराज में विकसित की गई बेहतरीन अवस्थापना सुविधाओं का सही ढंग से अनुरक्षण किया जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 मई, 2026 को जनपद प्रयागराज भ्रमण के अवसर पर नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल का लोकार्पण तथा 400 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने गंगा दशहरा के पावन पर्व और प्रयागराज नगर निगम कार्यकारिणी के तीन सफल वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में भावी विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए कि महाकुम्भ-2025 के सफल आयोजन के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा प्रयागराज में विकसित की गई बेहतरीन अवस्थापना सुविधाओं का सही ढंग से अनुरक्षण (रखरखाव) किया जाए, ताकि ये बुनियादी सुविधाएं अगले कुम्भ के समय हमारे लिए एक मजबूत धरोहर का कार्य कर सकें। उन्होंने अगले कुम्भ के वृहद आयोजन के लिए हजारों करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को समय से धरातल पर उतारने का स्पष्ट निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का निर्देश देते हुए कहा कि विरासत को विकास के साथ जोड़कर ही प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने प्रयागराज की सड़कों को और चौड़ी व स्मार्ट बनाने तथा विकास की इस अविरल धारा को हर मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए सभी पार्षदों को एक साथ मिलकर काम करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 'वेस्ट टू वेल्थ' की परिकल्पना को धरातल पर उतारते हुए नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सभी विकास कार्यों, जोनल पार्कों के निर्माण तथा शिवालय पार्क की नई श्रृंखलाओं की नियमित और कड़ी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्यों को सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि पूरे जनपद को भय, आतंक, माफियागिरी और गुण्डागर्दी से पूरी तरह मुक्त रखा जाए ताकि बेटियां, व्यापारी और आम नागरिक खुद को हमेशा सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने औद्योगिक गलियारों के निर्माण और बुनियादी ढांचे के बड़े कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका '3 साल बेमिसाल' का विमोचन किया तथा प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु तैयार की गई नवीन वेबसाइट का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने सफाईकर्मियों को सफाई किट देकर सम्मानित किया और नगर निगम के नए सफाई वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। समारोह को जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' ने भी सम्बोधित किया।

स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले हर सुधार का सीधा लाभ आम आदमी तक पहुँचना अनिवार्य : मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 मई, 2026 को लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले हर सुधार का सीधा लाभ आम आदमी तक पहुँचना अनिवार्य है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में इलाज, जाँच, दवाओं और आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता को लगातार बेहतर करने के सख्त निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने जोर देते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश को उच्च प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन्होंने सभी मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों तथा सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को आधुनिक तकनीक, कुशल मानव संसाधन और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से और अधिक सशक्त करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 108 जनपदीय चिकित्सालय, 106 विशिष्ट चिकित्सालय, 976 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3,757 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 27,668 स्वास्थ्य उपकेन्द्र पूरी सक्रियता से संचालित हैं। वर्ष 2025-26 की अवधि में सरकारी अस्पतालों द्वारा रिकॉर्ड 26.41 करोड़ ओ0पी0डी0 सेवाएं, 1.23 करोड़ आई0पी0डी0 सेवाएं तथा 24.33 करोड़ पैथोलॉजी जांचें आम जनता को उपलब्ध कराई गईं।

चिकित्सा शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 की स्थिति से तुलना करने पर सत्र 2025-26 तक प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 44 से बढ़कर 83 हो गई, जो कि 88.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त विगत 10 वर्षों में पी0जी0 सीटों की संख्या 1,344 से बढ़कर 5,067 हो गई, जबकि एम0बी0बी0एस0 की सीटें भी 5,390 से बढ़कर 12,800 के स्तर पर पहुँच गईं। सुपर स्पेशियलिटी सीटों के क्षेत्र में भी लगभग 165 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।बैठक में बताया गया कि नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में 652 संस्थान संचालित हैं और राज्य में लगभग 3.95 लाख पंजीकृत नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 'मिशन निरामया 1.0' के अन्तर्गत 17 हजार स्कूलों में परामर्श सत्र आयोजित कर 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँच बनाई गई और 10,570 नर्सिंग संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान योजना को गरीबों का सबसे बड़ा संबल बताते हुए इसके क्लेम दावों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अस्पतालों को समय पर भुगतान होता रहेगा, तो मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। वर्तमान में योजना से 6,480 अस्पताल संबद्ध हैं और अब तक 96.75 लाख से अधिक निःशुल्क उपचार किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री जी ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी आयुष पद्धतियों की आई0पी0डी0 सेवाओं को भी अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत कोविड कालखण्ड के दौरान सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का प्राथमिकता के आधार पर यथोचित समायोजन करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने आशा वर्करों के मानदेय भुगतान को किसी भी परिस्थिति में लंबित न रखने तथा हेल्थ ए0टी0एम0 सेवाओं का विस्तार सुदूर क्षेत्रों तक करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने तथा मातृ व शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को अत्यधिक मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री जी को बैठक में अवगत कराया गया कि डिजिटल स्वास्थ्य सुधारों के तहत 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' में 15.28 करोड़ से अधिक आभा आई0डी0 बनाई जा चुकी हैं और 15.14 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता देते हुए मेडिकल संस्थानों को रिसर्च आधारित स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। डिजिटल पहल के रूप में 'UP-IMRAS', मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, क्लिनिकल ट्रायल यूनिट तथा मेड-टेक कार्यक्रमों पर काम की गति तेज की गई है और इस क्षेत्र में लगभग 1,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए इंटेन्ट फाइल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बहुमंजिला गर्ल्स हॉस्टल, अयोध्या में 110 बेडेड ट्रॉमा सेन्टर, सहारनपुर में बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज तथा कानपुर मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विभाग विस्तार एवं डी-एडिक्शन वॉर्ड ब्लॉक जैसी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की रूपरेखा भी तय की गई। इस समय सार्वजनिक-निजी सहभागिता (PPP) मॉडल पर महराजगंज, शामली और सम्भल में मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।

आपातकालीन सेवाओं में लगे 375 एडवान्स्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेन्स के रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने संचालकों का भुगतान समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अस्पतालों में दवाओं की गुणवत्ता पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि तीन माह से कम एक्सपायरी अवधि वाली कोई भी दवा स्टॉक में नहीं रहनी चाहिए और उनकी जगह तत्काल नई दवाओं की आपूर्ति की जाए।मुख्यमंत्री जी को जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों में डायलिसिस सेवा और 74 जनपदों में सी0टी0 स्कैन सेवा उपलब्ध है, जिसके तहत मार्च 2026 तक 35.69 लाख से अधिक डायलिसिस सत्र और 45.35 लाख से अधिक सीटी स्कैन किए गए, जबकि 227 सी0एच0सी0 पर टेली-रेडियोलॉजी सेवा सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अब तक 376 से अधिक रोबोटिक सर्जरी तथा 250 से अधिक सफल किडनी प्रत्यारोपण किए गए और यहाँ प्रदेश का पहला गामा नाइफ सेंटर स्थापित करने तथा नए परिसर में 1,010 बेड क्षमता वाले अस्पताल के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जबकि एस0जी0पी0जी0आई0 में 500 बेड की क्षमता वाले एडवान्स पीडियाट्रिक सेन्टर परियोजना पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर मिशन, यू0पी0 ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क (UPTEN), प्रोजेक्ट सुश्रुत तथा CARE-UP मिशन की कार्ययोजनाओं का प्रस्तुतीकरण हुआ। मुख्यमंत्री जी ने टी0बी0 उन्मूलन अभियान को एक व्यापक जनआन्दोलन बनाने का आह्वान करते हुए इसमें शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिए; उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने संविदा पर कार्यरत एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि बेहतर चिकित्सक सरकारी सेवाओं से जुड़ें। उन्होंने अंत में स्पष्ट निर्देश दिए कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक, पूर्ण जवाबदेही और मानवीय संवेदनशीलता का एक साथ समावेश दिखना चाहिए, तभी आम लोगों का भरोसा और मजबूत हो सकेगा।